tres in Himachal Pradesh are as under:—

Location	Date of Sanction	Project Cost
Vill. Bhamla, Distt. Mandi.	11.12.1995	490.00
Vill. Gwalthai, Distt. Bilaspur	6.5.1997	432.00

The development work in respect of the IID Centre in Distt. Mandi is in progress and in respect of the Centre at Bilaspur, the land is being acquired.

उद्योगों की विकास दर

674. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ल:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल-दिसम्बर, 1998 के दौरान उद्योगों तथा निर्यात की विकास दर में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा विकास दर को पहले जैसी स्थिति में लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या चालू वर्ष में संगठित औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में भी तुलनात्मक कमी हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) और (ख) चालू वर्ष में अप्रैल-दिसंबर, 1998 के दौरान औद्योगिक विकास दर 3.5% रही है, जबकि अप्रैल-दिसंबर, 1997 में यह 6.7% थी। अप्रैल-दिसंबर, 1998 की अवधि में निर्यात विकास दर में (-) 2.88% की भारी गिरावट आई है। औद्योगिक विकास में आई इस गिरावट के कारक विश्व बाजार में सर्वत्र छाई मंदी के कारण निर्यात में कमी, कच्चा तेल, इस्पात, कोयला, सीमेंट, वाणिज्यिक वाहन, वस्त्र आदि की मांग में शिथिलता है। निर्यात में बढ़ने गिरावट हेतु कारक पूर्वी ऐशियाई देशों की मुद्रा का अत्यधिक अवमूल्यन से भारतीय निर्यातों के लिए प्रतियोगी हितों में कमी होना है।

(ग) से (ङ) औद्योगिक विकास में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

1. निर्यात में विकास की पुनरूज्जीवित करने हेतु विशेष पैकेज की घोषणा की गई है।

2. यूएलसीआरए को रद्द करना तथा गृह-स्वामित्व से संबंधित सुविधाएं देना।

3. निवेश को बढ़ावा देने तथा पूंजी बाजार के पुनरूज्जीवित करने के लिए सरकार ने हाल ही में शेयरों की पुनः खरीद तथा अंतःनिर्गम ऋण की अनुमति दी है।

4. भारतीय रिजर्व बैंक ने औद्योगिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए व्यस्ततम मौसम ऋण नीति के ब्याज दरों में वृद्धि करने से बचने के प्रयास किये है।

5. नई प्रौद्योगिकी को आरंभ करने, दक्षता सुधारने तथा गैर-महत्व के व्यवसायों से दूर रहने के लिए निजी क्षेत्र की पुनः संरचना की गई है। वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 की दूसरी तथा तीसरी तिमाही के लिए अधिकांश निगमों के वित्तीय परिणाम लागत में कमी दर्शाते हैं। पुनः संरचना के पश्चात, उनके द्वारा निवेश बढ़ाये जाने की संभावना है।

औद्योगिक क्षेत्र को पुनरूज्जीवित करने की आवश्यकता के प्रति सरकार जागरूक है और इसने गंभीर रूप से प्रभावित 4 क्षेत्रों नामतः इस्पात, पूंजीगत वस्तएं, वाणिज्यिक वाहनों तथा सीमेंट के लिए सुधारात्मक सिफारिशों की संस्तुति करते हुए 4 कार्यदलों का गठन किया है। कार्यदल की सिफारिशों की वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया है। इस्पात से संबंधित कतिपय उपायों की घोषणा कर दी गई है तथा अन्य क्षेत्रों से संबंधित नीतिगत घोषणा शीघ्र ही किये जाने की संभावना है।

1998-99 के रोजगार आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है। तथापि, सीएसओ के संकल घरेलू उत्पाद संबंधित अग्रिम अनुमानों से 1998-99 में जीडीपी में 5.8% की वृद्धि होने की आशा है, जिससे रोजगार में समग्र रूप से वृद्धि हो जाएगी।